UTTARAKHAND HIGHER JUDICIAL SERVICE

DIRECT RECRUITMENT EXAMINATION-2024

Maximum Marks: 100 **Time: 02 Hours**

Note:

i) All questions are compulsory.

ii) All the questions should be answered in one language (either Hindi or English).

Paper-II

CONSTITUTIONAL LAW (20 MARKS)

1. In March 2024, the Supreme Court of India, in a 7-judge bench, propounded the judgement of *Sita Soren v Union of India*, which overturned the 1998 *PV Narasimha Rao* judgement. Which constitutional principles are touched upon by Article 105 and 194 of the Constitution of India? Discuss the ratio of the *Sita Soren* judgement and analyse it vis-à-vis the *PV Narasimha Rao* judgement.

मार्च २०२४ में सुप्रीम कोर्ट ने ७ जजों की बेंच द्वारा *सीता सोरेन बनाम भारत संघ* के फैसले को पेश किया, जिसने १९९८ के *पीवी नरसिम्हा राव* के फैसले को पलट दिया। भारत के संविधान के अनुच्छेद १०५ और १९४ में किन संवैधानिक सिद्धांतों का वर्णन है? *सीता सोरेन* के फैसले पर चर्चा करें और *पीवी नरसिम्हा राव* के फैसले के साथ इसका विश्लेषण करें।

[05 Marks]

2. What is the Doctrine of Legitimate Expectation? The Supreme Court in different instances has laid down the crucial features regarding the Doctrine of Legitimate Expectation. Enumerate the same by referring to settled case laws.

वैध अपेक्षा का सिद्धांत क्या है? सर्वोच्च न्यायालय ने कई अलग-अलग मामलों में वैध अपेक्षा के सिद्धांत की महत्वपूर्ण विशेषताएं निर्धारित की हैं। निर्णयजन्य विधि का प्रमाण देते हुए उत्तर दें।

[05 Marks]

3. In 2015, Jamshedbhai Lohawaale, a famous Indian industrialist, founded an airline company named 'Bhartiya Air Services' with the help of the Government of India through the Public Private Partnership (PPP) mode, wherein 30% of the total seed capital required for the airline was raised by the government, and the rest was raised privately by Lohawaale.

The airline continued to function normally. However, in 2018, following a series of strikes by airline staff over non-payment of salaries, 12 of the striking employees were terminated. Aggrieved by their termination, these employees filed a writ petition at their state's High Court against the airline company, seeking redressal.

While this case was sub-judice, the Government of India, in an unrelated turn of events, decided to disinvest its stake in Bhartiya Air Services, leading to its privatisation.
Due to this privatisation, the lawyers for the airline moved an application to the High Court stating that since the company is now a private entity, the Writ Petition filed by the employees is now not maintainable.

On the basis of the above information, discuss the meaning of 'State' as per Article 12 of the Constitution of India. Evaluate the facts of the above case and decide whether the said Writ Petition will be maintainable following the privatisation of the company. Support your answer with the most recent case laws.

OR

Kokilaben Pande and Manoj Pande got married as per Hindu traditions in 2001 and lived a happy married life. Unfortunately, six years into their marriage, Manoj suffered a stroke which rendered him comatose.

Kokilaben, being a dutiful wife, took complete care of her husband and all his medical needs. However, as the years passed, she found it difficult to look after his affairs as she had no legal right to take care of his property, manage his bank accounts, and sign documents on his behalf. Aggrieved by this, Kokilaben moved a Writ Petition at her state's High Court seeking legal guardianship of her husband in order to better manage his estate and affairs.

Examine the abovementioned case in light of Article 21 of the Constitution of India. Decide whether the High Court is empowered to grant her relief or not. What are the guidelines, if any, that need to be considered in such a case? Answer on the basis of settled case laws.

२०१५ में एक प्रसिद्ध भारतीय उद्योगपति जमशेदभाई लोहावाले ने भारत सरकार की मदद से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड के तहत 'भारतीय एयर सर्विसेज' नामक एक एयरलाइन कंपनी की स्थापना की, जिसमें एयरलाइन के लिए आवश्यक कुल बीज पूंजी का ३०% सरकार द्वारा जुटाया गया था, और बाकी लोहावाले द्वारा निजी तौर पर जुटाया गया था।

इस दौरान एयरलाइन सामान्य रूप से काम करती रही। परंतु २०१८ में वेतन का भुगतान न करने पर एयरलाइन कर्मचारियों द्वारा हड़ताल की गई और १२ हड़ताली को बर्खास्त कर दिया गया था। अपनी बर्खास्तगी से व्यथित होकर इन कर्मचारियों ने अपने राज्य के उच्च न्यायालय में एयरलाइन कंपनी के खिलाफ एक रिट याचिका दायर की और निवारण की मांग की।

जब यह मामला विचाराधीन था, तब भारत सरकार ने एक असंबंधित घटनाक्रम के तहत भारतीय एयर सर्विसेज में अपनी हिस्सेदारी का विनिवेश करने का फैसला किया जिसके परिणामस्वरूप इसका निजीकरण हो गया।
इस निजीकरण के कारण एयरलाइन के वकीलों ने उच्च न्यायालय में एक आवेदन दायर किया जिसमें यह कहा गया कि चूंकि कंपनी अब एक निजी संस्था है, अतः कर्मचारियों द्वारा दायर रिट याचिका अब संधार्य नहीं है।

उपरोक्त जानकारी के आधार पर भारत के संविधान के अनुच्छेद १२ के अनुसार 'राज्य' के अर्थ पर चर्चा करें। उपरोक्त मामले के तथ्यों का मूल्यांकन करें और तय करें कि कंपनी के

निजीकरण के बाद उक्त रिट याचिका विचारणीय होगी या नहीं। अपने उत्तर का नवीनतम निर्णयजन्य विधि द्वार समर्थित करें।

अथवा

कोकिलाबेन पांडे और मनोज पांडे ने २००१ में हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार विवाह किया और एक खुशहाल वैवाहिक जीवन व्यतीत किया। दुर्भाग्यवश, विवाह के छह साल बाद मनोज को स्ट्रोक का सामना करना पड़ा जिससे वह कोमा में चले गए।

एक कर्तव्यनिष्ठ पत्नी होने के नाते कोकिलाबेन ने अपने पति और उनकी सभी चिकित्सा हेतु आवश्यकताओं का पूरा ध्यान रखा। परंतु जैसे-जैसे साल बीतते गए, उन्हें अपने पति के मामलों की देखभाल करना मुश्किल लगने लगा, क्योंकि उन्हें उनकी संपत्ति की देखभाल करने, उनके बैंक खातों का प्रबंधन करने, और उनकी ओर से दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। इससे व्यथित होकर कोकिलाबेन ने अपने पति की संपत्ति और मामलों को बेहतर ढंग से प्रबंधित करने के लिए उनके कानूनी संरक्षकता की मांग करते हुए अपने राज्य के उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की।

भरत के संविधान के अनुच्छेद २१ का वर्णन करते हुए उपर्युक्त मामले की जाँच करें। तय करें कि उच्च न्यायालय को उन्हें राहत देने का अधिकार है या नहीं। ऐसे मामले में किन दिशा-निर्देशों पर विचार करने की आवश्यकता है? निर्णयजन्य विधि का प्रमाण देते हुए उत्तर दें।

[10 Marks]

Criminal Law (40 Marks)

4. Answer the following in brief:

   a) What is meant by 'Plea Bargaining'? Discuss its relevance in the Indian justice system.

   b) Who is a 'Support Person' as per the Protection of Children from Sexual Offences Rules, 2020? Discuss their importance.

c) In what circumstances can a person be arrested under the Prevention of Money Laundering Act, 2002?

d) What is the Doctrine of Necessity?

e) Compare 'Retributive Justice' and 'Reformative Justice'.

निम्नलिखित का संक्षेप में उत्तर दें:

a) 'दलील सौदेबाज़ी' का क्या अर्थ है? भारतीय न्याय प्रणाली में इसकी प्रासंगिकता पर चर्चा करें।

b) लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण नियम, २०२०, के अनुसार 'सहायक व्यक्ति' कौन है? उनके महत्व पर चर्चा करें।

c) किन परिस्थितियों में किसी व्यक्ति को धन शोधन निवारण अधिनियम, २००२ के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है?

d) आवश्यकता का सिद्धांत क्या है?

e) 'प्रतिशोधात्मक न्याय' और 'सुधारात्मक न्याय' की तुलना करें।

[02x5=10 Marks]

5. In July 2022, the Apex Court pronounced the landmark judgement of *Satender Kumar Antil v Central Bureau of Investigation,* wherein issues related to bail jurisprudence and the rights of an accused were discussed inter alia. In light of the aforementioned, discuss the challenges faced with respect to the law of bail in the Indian justice system and critically examine the role played by *Satender Kumar Antil* in overcoming the same.

जलाई २०२२ में सर्वोच्च न्यायालय ने *सतेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो* का ऐतिहासिक फैसला सुनाया, जिसमें जमानत न्यायशास्त्र और अभियुक्त के अधिकारों से संबंधित मुद्दों पर अन्य बातों के साथ-साथ चर्चा की गई थी। उपर्युक्त के तहत भारतीय न्याय प्रणाली में जमानत के कानून से संबंधित चुनौतियों पर चर्चा करें और उन पर काबू पाने में *सतेंद्र कुमार अंतिल* द्वारा निभाई गई भूमिका की आलोचनात्मक जांच करें।

[05 Marks]

6. Discuss the interplay between the right of a divorced Muslim woman to seek maintenance under Section 144 of the Bhartiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023, and the same right as provided under the Muslim Women (Protection of Rights on Divorce) Act, 1986. Are these two laws in derogation of, or in addition to, each other? Answer by citing relevant case laws.

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, २०२३, की धारा १४४ के तहत एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला के भरण-पोषण की मांग करने के अधिकार और मुस्लिम महिला (तलाक पर अधिकारों का संरक्षण) अधिनियम, १९८६, के तहत दिए गए समरूपी अधिकार के अंतर्सम्बन्ध पर चर्चा करें। क्या ये दोनों कानून एक दूसरे के अपवाद हैं या एक दूसरे के अतिरिक्त हैं? निर्णयजन्य विधि का प्रमाण देते हुए उत्तर दें।

[05 Marks]

7. Under the Prevention of Atrocities Act, 1989, what is meant by 'intent to insult'? If an insult to a person lacks an intention to humiliate based on caste identity, can said insult be considered as an offence under the Prevention of Atrocities Act, 1989? Discuss with the help of relevant case laws.

अत्याचार निवारण अधिनियम, १९८९, के तहत 'अपमान करने के इरादे' का क्या अर्थ है? अगर किसी व्यक्ति का अपमान जातिगत पहचान के आधार पर अपमानित करने के इरादे से नहीं किया जाता है, तो क्या उक्त अपमान को अत्याचार निवारण अधिनियम, १९८९, के तहत अपराध माना जा सकता है? निर्णयजन्य विधि का प्रमाण देते हुए उत्तर दें।

[05 Marks]

8. What is meant by socio-economic offences? How are they different from civil disputes? Can economic offences involving corruption and loss to public exchequer be quashed on the basis of a settlement? Answer by citing relevant case laws.

सामाजिक-आर्थिक अपराधों का क्या अर्थ है? वे सिविल विवादों से किस तरह अलग हैं? क्या भ्रष्टाचार और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने वाले आर्थिक अपराधों को समझौते के आधार पर रद्द किया जा सकता है? निर्णयजन्य विधि का प्रमाण देते हुए उत्तर दें।

[05 Marks]

9. Yakub Jaffar Afridi was arrested by the police under sections 15 and 16 of the Unlawful Activities Prevention Act, 1976. It is pertinent to note here that the investigation of this case was assigned to the National Investigation Agency by the State.

The accused applied for bail at the local Sessions Court, which was duly rejected. Aggrieved by this, the accused approached the High Court and filed a bail application against the order of the Sessions Court.

When the case came before a single judge bench of the High Court, the State's counsel argued that the bail application was not maintainable. They cited Section 21 of the National Investigation Agency Act, 2008, which mandates that any application challenging an order of the Special Court must be heard by a division bench of the High Court. In response, the accused's counsel contended that the NIA Act, 2008, only talks about a Special Court, and not a Sessions Court, due to which the argument of the State's counsel was entirely without merit. Subsequently, the State's counsel clarified that since no Special Court has been designated by the State, the Sessions Court has jurisdiction in this matter.

In light of the aforementioned, determine whether an application against the order dismissing the bail application passed by the Sessions Court shall be considered as a bail application or an appeal? Furthermore, does a Sessions Court have jurisdiction to try the instant case when the State has not designated any Special Court? Finally, decide whether the instant bail application is maintainable or not before a single judge bench of the High Court. Provide well-reasoned answers underpinned by existing case laws.

OR

Deep is a businessman who deals with arts and craft products. During the course of his business, he entered into an agreement with Sameer wherein Sameer delivered some raw materials to Deep and Deep wrote Sameer a cheque of ₹2 lakhs in the form of a security for the payment of the outstanding debt. Sameer encashed this cheque, which bounced. When the cheque bounced, Deep filed a civil suit against Sameer, wherein his counsel argued that Sameer should be restrained from encashing said cheque as it was meant for security

purposes and not for encashment. This argument was accepted by the Civil Court and decreed the suit in Deep's favour.

In the meantime, Sameer initiated cheque bounce proceedings against Deep under section 138 of the Negotiable Instruments Act, 1881. When these proceedings were being heard, Deep's counsel submitted that since Sameer has been restrained from encashing the cheque by the Civil Court, the very object of the cheque bounce case stands vitiated. Sameer's counsel responded by stating that civil and criminal laws are two distinct realms, and the decrees of the Civil Court will not be binding on the present criminal proceedings. Herein, Deep was found guilty and an appeal was preferred in the High Court against this conviction.

Based on the above information, determine whether the decision of the Civil Court is a relevant consideration in the criminal proceedings. To what extent are civil proceedings divorced from criminal proceedings? Discuss the effect of civil proceedings in a criminal proceeding wherein the substance of the dispute in both is the same? In light of the same, decide what should be the High Court's decision? Give reasons for your decision based on relevant case laws.

याकूब जाफर अफरीदी को पुलिस ने विधिविरूद्ध क्रिया-कल्प (निवारण) अधिनियम, १९७६, की धारा १५ और १६ के तहत गिरफ्तार किया था। यह ध्यान देने योग्य है कि इस मामले की जांच राज्य द्वारा राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंपी गई थी।

आरोपी ने स्थानीय सत्र न्यायालय में जमानत के लिए आवेदन किया, जिसे विधिवत खारिज कर दिया गया। इससे व्यथित होकर, आरोपी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और सत्र न्यायालय के आदेश के खिलाफ जमानत याचिका दायर की।

जब मामला उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश पीठ के समक्ष आया, तो राज्य के वकील ने तर्क दिया कि जमानत याचिका संधार्य नहीं है। उन्होंने राष्ट्रीय जांच एजेंसी अधिनियम, २००८, की धारा २१ का हवाला दिया, जिसमें यह अनिवार्य है कि विशेष न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाले किसी भी आवेदन पर उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा सुनवाई की जानी चाहिए। जवाब में आरोपी के वकील ने तर्क दिया कि एनआईए अधिनियम, २००८, केवल विशेष न्यायालय की बात करता है, न कि सत्र न्यायालय की, जिसके कारण राज्य के

वकील का तर्क पूर्णतः अमान्य है। राज्य के वकील ने स्पष्ट किया कि चूंकि राज्य द्वारा कोई विशेष न्यायालय नामित नहीं किया गया है, अतः इस मामले में सत्र न्यायालय का क्षेत्राधिकार है।

उपर्युक्त के तहत निर्धारित करें कि सत्र न्यायालय द्वारा पारित जमानत आवेदन को खारिज करने के आदेश के खिलाफ आवेदन को जमानत याचिका माना जाएगा या अपील माना जाएगा? अगर राज्य ने कोई विशेष न्यायालय नामित नहीं किया है तो क्या सत्र न्यायालय के पास इस मामले की सुनवाई करने का अधिकार है? अंत में यह तय करें कि इस जमानत आवेदन उच्च न्यायालय की एकल न्यायाधीश पीठ के समक्ष विचारणीय है या नहीं। निर्णयजन्य विधि का प्रमाण देते हुए उत्तर दें।

अथवा

दीप एक व्यवसायी है जो कला और शिल्प उत्पादों का कारोबार करता है। अपने कारोबार के दौरान उसने समीर के साथ एक समझौता किया जिसके तहत समीर ने दीप को कुछ कच्चा माल दिया और दीप ने बकाया कर्ज के भुगतान के लिए प्रतिभूति के तौर पर समीर को ₹२ लाख का चेक लिखा। समीर ने इस चेक को भुनाया, जिसका अनादर हो गया। जब चेक का अनादर हुआ तो दीप ने समीर के खिलाफ एक सिविल मुकदमा दायर किया, जिसमें उसके वकील ने तर्क रखा कि समीर को उक्त चेक को भुनाने से रोका जाना चाहिए क्योंकि यह चेक प्रतिभूति के उद्देश्यों के लिए था न कि भुनाने के लिए। इस तर्क को सिविल कोर्ट ने स्वीकार कर लिया और दीप के पक्ष में फैसला सुनाया।

इस बीच, समीर ने परक्राम्य लिखत अधिनियम ,१८८१, की धारा १३८ के तहत दीप के खिलाफ चेक के अनादर की कार्यवाही शुरू की। सुनवाई के दौरान दीप के वकील ने तर्क रखा कि चूंकि समीर को सिविल कोर्ट द्वारा चेक भुनाने से रोका गया है इसलिए चेक अनादर मामले का मूल उद्देश्य ही समाप्त हो गया है। समीर के वकील ने जवाब दिया कि सिविल और क्रिमिनल कानून दो अलग-अलग क्षेत्र हैं और सिविल कोर्ट के फैसले मौजूदा आपराधिक कार्यवाही पर बाध्यकारी नहीं होंगे। इस मामले में दीप को दोषी पाया गया और इस सजा के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की गई।

उपर्युक्त जानकारी के आधार पर निर्धारित करें कि क्या आपराधिक कार्यवाही में सिविल कोर्ट का फैसला प्रासंगिक माना जाएगा या नहीं। किस हद तक सिविल कार्यवाही आपराधिक कार्यवाही से अलग है? आपराधिक कार्यवाही में सिविल कार्यवाही के प्रभाव पर चर्चा करें, जिसमें दोनों में विवाद का सार एक ही है? इसके आधार पर तय करें कि हाई कोर्ट को क्या निर्णय लेना चाहिए? निर्णयजन्य विधि का प्रमाण देते हुए उत्तर दें।

[10 Marks]

Civil Law (40 Marks)

10. Answer the following in brief:

a) Discuss the role of Lok Adalats in resolving civil disputes.

b) What is meant by 'Sufficient Cause' as provided under the Limitation Act, 1963.

c) What is meant by Second Appeal? Enumerate the powers of the Appellate Court with regard to Second Appeal.

d) Differentiate between void and voidable agreement under Indian contract law.

e) What is an interpleader suit?

निम्नलिखित का संक्षेप में उत्तर दें:

a) सिविल विवादों को सुलझाने में लोक अदालतों की भूमिका पर चर्चा करें।

b) सीमा अधिनियम, 1963 के तहत 'पर्याप्त कारण' का क्या अर्थ है।

c) द्वितीय अपील का क्या अर्थ है? द्वितीय अपील के संबंध में अपीलीय न्यायालय की शक्तियों का उल्लेख करें।

d) भारतीय अनुबंध कानून के तहत शून्य और शून्यकरणीय समझौते के बीच अंतर करें।

e) अंतराभिवाची वाद क्या होता है?

[02x5=10 Marks]

11. What is the time limit for an arbitral award as prescribed under Section 29A of the Arbitration and Conciliation Act, 1996? How does the application of this section differ in the case of a domestic arbitration as opposed to an international arbitration? Discuss with the help of case laws.

मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, १९९६, की धारा २९-अ के तहत निर्धारित मध्यस्थता पुरस्कार के लिए समय सीमा क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के विपरीत घरेलू मध्यस्थता के मामले में इस धारा का अनुप्रयोग किस प्रकार भिन्न है? निर्णयजन्य विधि का प्रमाण देते हुए उत्तर दें।

[05 Marks]

12. What are pleadings as per the Code of Civil Procedure, 1908? Briefly discuss Order VI of the Code of Civil Procedure, 1908. In case the plaintiff is seeking alternative reliefs, is he entitled to file inconsistent pleas? Answer on the basis of settled case laws.

सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८, के अनुसार दलीलें क्या हैं? सिविल प्रक्रिया संहिता, १९०८, के आदेश VI पर संक्षेप में चर्चा करें। यदि वादी वैकल्पिक राहत की मांग कर रहा है, तो क्या वह असंगत दलीलें दायर कर सकता है? निर्णयजन्य विधि का प्रमाण देते हुए उत्तर दें।

[05 Marks]

13. What is meant by adverse possession? What is the law surrounding a claim of adverse possession? What kind of possession does a tenant have against their landlord? Can a tenant claim adverse possession against their landlord? Answer on the basis of settled case laws.

प्रतिकूल कब्जे का क्या मतलब है? प्रतिकूल कब्जे के दावे से संबंधित कानून क्या है? एक किरायेदार का अपने मकान मालिक के खिलाफ किस तरह का कब्ज़ा है? क्या एक किरायेदार अपने मकान मालिक के खिलाफ प्रतिकूल कब्जे का दावा कर सकता है? निर्णयजन्य विधि का प्रमाण देते हुए उत्तर दें।

[05 Marks]

14. What is a commercial dispute as per the Commercial Courts Act, 2015? Can a dispute involving an immovable property be considered as a commercial dispute? If so, under what circumstances? Answer on the basis of settled case law.

वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम, 2015 के अनुसार वाणिज्यिक विवाद क्या है? क्या अचल संपत्ति से जुड़े विवाद को वाणिज्यिक विवाद माना जा सकता है? यदि हाँ, तो किन परिस्थितियों में? निर्णयजन्य विधि का प्रमाण देते हुए उत्तर दें।

[05 Marks]

15. Al-Khameri, a UAE based construction firm, was approached by Barons Ltd. for a telecommunications project in India. For the same, an MoU was signed between the two in 2004, under which Barons Ltd. would periodically finance Al-Khameri for the construction work, inter alia. In 2011, three cheques which were for financing the project, each worth ₹7 crores, bounced and Al-Khameri moved against Barons Ltd under 138 of the Negotiable Instruments Act, 1881.

These proceedings dragged on all the way to 2024. Aggrieved by this, Al-Khameri sent Barons Ltd. a notice invoking arbitration under a clause of the MoU. When the notice went unanswered, Al-Khameri filed a petition under Section 11(6) of the Arbitration and Conciliation Act, 1996.

The counsel for Barons Ltd argued before the Court that the present petition filed by Al-Khameri is time barred and hence should be disposed of accordingly. The counsel for Al-Khameri submitted that given the proceedings under the NI Act were still ongoing, the same should be considered as an ongoing cause of action, and hence not barred by limitation.

In light of the aforementioned, what is meant by 'cause of action'? Can a MoU be considered as an arbitration agreement? When a notice for invoking arbitration proceedings goes unanswered, how does Section 11 of the Arbitration and Conciliation Act, 1996, come to the rescue of the party invoking arbitration? In the present case, what should be the decision of the Court? Justify your answer using settled case laws.

OR

Sonu and Sara had been dating for the past 10 years. One day, they decided to get married and threw a big party for all their friends. This party was a grand affair. There was a lot of song and dance, and every guest was wined and dined extravagantly. Following this party, Sonu and Sara went to their local Registrar to get a marriage certificate under the Hindu Marriage Act, 1955, which was duly granted.

A few days later, the newlyweds applied for a joint loan at a bank to buy a new home. They applied for the loan as husband and wife in order to get a lower interest rate as advertised by the bank. However, while the loan was being processed, the loan officer informed them that they are not eligible for the joint spousal loan because their marriage was invalid as per the Hindu Marriage Act, 1955.

Aggrieved by this, the couple again presented their marriage registration to the bank. The bank duly rejected said document by saying that their marriage was invalid as it did not follow the proper customs as mandated in the Hindu Marriage Act, 1955.

One the basis of the abovementioned information, discuss the importance of the ceremonies for a Hindu Marriage as laid down under Section 7 of the Hindu Marriage Act, 1955. Can a marriage be validly registered as a Hindu Marriage without such ceremonies? What is the effect on such a marriage by the registration of the same as laid down under Section 8 of the Act? Decide on the basis of settled case laws.

यूएई स्थित निर्माण फर्म अल-खमेरी को बैरन्स लिमिटेड ने भारत में एक दूरसंचार परियोजना के लिए संपर्क किया था। इसके लिए २००४ में दोनों के बीच एक समझौता ज्ञापन किए गया जिसके तहत बैरन्स लिमिटेड समय-समय पर निर्माण कार्य के लिए अल-खमेरी को वित्तपोषित करेगा। २०११ में तीन चेक जो परियोजना के वित्तपोषण के लिए थे, जिनमे प्रत्येक की कीमत ₹७ करोड़ थी, उनका अनादर हो गए और अल-खमेरी ने परक्राम्य लिखत अधिनियम,१८८१, की धारा १३८ के तहत बैरन्स लिमिटेड के खिलाफ मुकदमा दायर किया।
ये कार्यवाही २०२४ तक चलती रही। इससे व्यथित होकर, अल-खमेरी ने बैरन्स लिमिटेड को समझौता ज्ञापन के एक खंड के तहत मध्यस्थता का आह्वान करते हुए एक नोटिस भेजा।

नोटिका का जवाब ना मिलने पर अल-खमेरी ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, १९९६ की धारा ११(६) के तहत याचिका दायर की।

बैरन्स लिमिटेड के वकील ने न्यायालय के समक्ष तर्क दिया कि अल-खमेरी द्वारा दायर वर्तमान याचिका समय सीमा से बाहर है और इसलिए इसे ख़ारिज कर देना चाहिए। अल-खमेरी के वकील ने प्रस्तुत किया कि चूंकि एनआई अधिनियम की कार्यवाही अभी भी विचाराधीन है, इसलिए इन्हें अविरीत वाद-हेतुक माना जाना चाहिए और सीमा द्वारा वर्जित नहीं माना जाना चाहिए।

उपर्युक्त के प्रकाश में बतायें कि 'वाद-हेतुक' का क्या अर्थ है? क्या समझौता ज्ञापन को मध्यस्थता समझौता माना जा सकता है? जब मध्यस्थता कार्यवाही शुरू करने के लिए नोटिस का जवाब नहीं मिलता है, तो मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, १९९६ की धारा ११ मध्यस्थता का आह्वान करने वाले पक्ष के बचाव में कैसे आती है? प्रस्तुत मामले में न्यायालय का निर्णय क्या होना चाहिए? निर्णयजन्य विधि का प्रमाण देते हुए उत्तर दें।

अथवा

सोनू और सारा पिछले १० सालों से डेट कर रहे थे। एक दिन उन्होंने शादी करने का फैसला किया और अपने सभी दोस्तों के लिए एक बड़ी पार्टी रखी। यह पार्टी बहुत शानदार थी। खूब नाच-गाना हुआ और हर मेहमान को खूब खिलाया-पिलाया गया। इस पार्टी के बाद सोनू और सारा हिंदू विवाह अधिनियम, १९५५, के तहत विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अपने स्थानीय रजिस्ट्रार के पास गए और उन्हें प्रमाण पत्र विधित रूप से प्रदान किया गया।

कुछ दिनों बाद नवविवाहित जोड़े ने नया घर खरीदने के लिए बैंक में संयुक्त ऋण के लिए आवेदन किया। उन्होंने बैंक द्वारा विज्ञापित कम ब्याज दर प्राप्त करने के लिए पति-पत्नी के रूप में ऋण के लिए आवेदन किया। हालाँकि जब ऋण संसाधित किया जा रहा था, तो ऋण अधिकारी ने उन्हें सूचित किया कि वे संयुक्त पति-पत्नी ऋण के लिए मान्य नहीं हैं क्योंकि हिंदू विवाह अधिनियम, १९५५, के अनुसार उनका विवाह अमान्य था।

इससे व्यथित होकर जोड़े ने बैंक में अपना विवाह पंजीकरण पुनः प्रस्तुत किया। बैंक ने उक्त दस्तावेज को विधिवत खारिज कर दिया और कारण रखते हुए कहा कि उनका विवाह अवैध है क्योंकि इसमें हिंदू विवाह अधिनियम, १९५५, में वर्णित उचित रीति-रिवाजों का पालन नहीं किया गया है।

उपर्युक्त जानकारी के आधार पर हिंदू विवाह अधिनियम, १९५५, की धारा ७ के तहत निर्धारित हिंदू विवाह के लिए अनुष्ठानों के महत्व पर चर्चा करें। क्या ऐसे उचित रीति-रिवाजों के बिना विवाह को हिंदू विवाह के रूप में वैध तौर से पंजीकृत किया जा सकता है? अधिनियम की धारा ८ के तहत निर्धारित पंजीकरण से ऐसे विवाह पर क्या प्रभाव पड़ता है? निर्णयजन्य विधि का प्रमाण देते हुए उत्तर दें।

[10 Marks]